UN HIGH SEAS TREATY

Negotiations involving 168 countries, including the European Union, to agree on a UN High Seas Treaty for protecting oceans failed.

What are the High seas?

- The high seas are the vast open ocean and deep seabed areas found beyond any country's national jurisdiction.
- They hold great biodiversity but also remain the least-protected areas.

Key Points

About UN High Seas Treaty

- It is also referred to as the **'Paris Agreement for the Ocean'.**
- It is a proposed treaty **to deal with Biodiversity** Beyond National Jurisdiction.
- The treaty was to be negotiated under the **United Nations Convention on Laws of the Sea (UNCLOS)** of 1982.
- It concerns the ocean existing beyond the Exclusive Economic Zones, till where a country has special rights for exploration.
- Some aspects of negotiations under the treaty include establishing marine protected areas to put limits on certain activities such as
  - environmental impact assessments, financial support to countries and sharing other scientific knowledge.
- Conversely, every country has the right to access open seas, resulting in large-scale drilling and trawling operations for catching fish and other animals for commercial purposes.

UNCLOS & Regulation of World's Oceans:

- UNCLOS governs the rights of countries regarding marine resources.
- It regulates the conduct on the high seas.
- It led to the establishment of territorial sea boundaries 22 km offshore, deciding the region up to which countries could claim full sovereign territorial rights.

- It also created the International Seabed Authority and other conflict-resolution mechanisms.
- But a treaty dedicated to protecting ocean health does not exist as of now.

Exclusive Economic Zone (EEZ):

- An EEZ is a region in which a nation has special rights in terms of marine resource exploration and use.
- These regions are adjacent and beyond a country's territorial waters and do not extend beyond 200 nautical miles (nmi) from a nation's coast.
- These exclusive economic zones also include the continental shelf within the 200 nmi limit.

संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि

महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि पर सहमत होने के लिए यूरोपीय संघ सहित 168 देशों की बातचीत विफल रही।

उच्च समुद्र क्या हैं?

- देश अपनी तट रेखाओं तक 200 समुद्री मील (370 किलोमीटर) के भीतर समुद्री सीमा में सुरक्षा या दोहन कर सकते हैं,लेकिन इन 'विशेष आर्थिक क्षेत्र ' के बाहर का सारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र उच्च समुद्र माना जाता है।

प्रमुख बिंदु

संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि के बारे में

- इसे 'महासागर के लिए पेरिस समझौता' भी कहा जाता है।
- यह राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता से निपटने के लिए एक प्रस्तावित संधि है।
- इस संधि पर 1982 के समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत बातचीत की जानी थी।
- यह विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों , जहां तक किसी देश के पास अन्वेषण के विशेष अधिकार हैं उससे परे विद्यमान महासागर से संबंधित हैं।
- संधि के तहत बातचीत के कुछ पहलुओं में कुछ गतिविधियों पर सीमा लगाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना शामिल है जैसे कि
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, देशों को वित्तीय सहायता और अन्य वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना।
- इसके विपरीत, प्रत्येक देश को खुले समुद्र तक पहुँचने का अधिकार है, जिसके परिणामस्वरूप व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए मछली और अन्य जानवरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग और ट्रॉलिंग ऑपरेशन होते हैं।

UNCLOS और विश्व के महासागरों का विनियमन:

- UNCLOS समुद्री संसाधनों के संबंध में देशों के अधिकारों को नियंत्रित करता है।
- यह उच्च समुद्रों पर आचरण को नियंत्रित करता है।
- इसने 22 किमी अपतटीय क्षेत्रीय समुद्री सीमाओं की स्थापना की स्थापना की, उन क्षेत्रों की सीमा को तय की जिनमे देश पूर्ण संप्रभु क्षेत्रीय अधिकारों का दावा कर सकते हैं।

- इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण और अन्य संघर्ष-समाधान तंत्र भी बनाए।
- लेकिन समुद्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए समर्पित एक संधि अभी मौजूद नहीं है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ):

- EEZ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक राष्ट्र के पास समुद्री संसाधन अन्वेषण और उपयोग के मामले में विशेष अधिकार होते हैं।
- ये क्षेत्र एक देश के प्रादेशिक समुद्र से अलग है लेकिन सटा हुआ है जिसकी दूरी किसी देश के तट से 200 समुद्री मील (nmi) से अधिक नहीं हैं।
- इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में 200 (nmi) सीमा के भीतर महाद्वीपीय शेल्फ भी शामिल है।